POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 04

मासिक प्रेषण दि. 8 अप्रेल, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अप्रेल, 2019 मूल्य 50 पैसे

बाल सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण भावी विकास के दो मुख्य स्तम्भ : मेनका गांधी

'बाल सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण देश के भावी विकास के दो मुख्य स्तम्भ हैं। इस आधी आबादी द्वारा भारत की प्रगति और विकास में दिए गए मूल्यवान योगदान की यूं ही उपेक्षा नहीं की जा सकती।' केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 'कट्स' द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'स्टोरीज ऑफ चेंज' पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह कहा।

उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के ज्यादातर गांवों में बाल सुरक्षा व महिलाओं के लिए व्यावसायिक अवसर पैदा करने में 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में पुरुष वर्ग को बालिका सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर और अधिक संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक असमानताओं को मात्र अवसरों की समानता लाकर ही दूर किया जा सकता है।

इस अवसर पर 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप महता ने कहा कि जब महिला सशक्त होती है तो इसका सीधा लाभ परिवार को मिलता है एवं उत्तरोत्तर प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचता है। 'स्टोरीज ऑफ चेंज' पुस्तक में 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा पिछले 25 वर्षों में राजस्थान में जमीनी स्तर पर बाल सुरक्षा एवं स्वयं सहायता समूहों के गठन में दिए गए सक्रिय योगदान तथा महिलाएं किस तरह आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनी हैं, के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया है। परिचर्चा के दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए।

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

ग्राहक सावधान! मिलावट-खोर अपने फायदे के लिए इंसानों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। पिछले कई सालों से प्रदेश में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इससे आमजन बुरी तरह से पीड़ित हैं।

बड़ी तादात में मावा, पनीर, देशी घी जैसे खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि गंभीर बीमारियों में काम में ली जाने वाली कई दवाएं तक नकली बिकती पाई गई हैं।

यहां तक कि रोजाना काम में आने वाले आटा, बेसन, दालें, मसालें और नमक आदि तक सुरक्षित नहीं हैं। इनमें खतरनाक वस्तुओं, अखाद्य सिथेंटिक रंगों और अन्य रासायनिक पदार्थों की मिलावट होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कमाई के फेर में उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने वाली ऐसी कई फर्मों, लोगों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मार कर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है।

देखा गया है, हमारी सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारी तब ही हरकत में आते हैं, जब समाचार पत्रों में खबरें छपती हैं। इसके बाद कुछ ही दिनों तक इसके खिलाफ अभियान चलता है और मामला ठंड़ा पड़ जाता है। सख्त कार्रवाई और सजा नहीं होने से पकड़े गए अपराधियों में कोई भय तक दिखाई नहीं देता। प्रदेश में 50 लाख खाद्य व्यापारियों के बीच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या मात्र 73 है।

मुझे खुशी है, पिछले दिनों राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और संबंधित विभागों से इस बारे में जवाब भी मांगा है। राज्य सरकार ने भी मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का मानस बनाया है।

पेट में छोड़ दी थी कैंची, देना होगा हर्जाना

बीकानेर निवासी पूनम ने जिला उपभोक्ता मंच में डॉ. इति माथुर, टी. फिलिक एवं माथुर हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर, रानी बाजार के खिलाफ परिवाद दायर किया। परिवाद में कहा गया कि वह गर्भवती थी। उसने 25 फरवरी, 2013 को रानी बाजार निवासी डॉ. इति माथुर से जांच कराई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉ. इति माथुर ने ऑपरेशन किया। उसने बच्ची को जन्म दिया। घर आने के बाद पूनम के पेट में दर्द रहने लगा, तो पीबीएम अस्पताल में अन्य चिकित्सक को दिखाया। तब पता चला कि उनके पेट में कैंची छोड़ दी गई थी। पीएनबी अस्पताल में ऑपरेशन कर उसके पेट से कैंची निकाली गई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने इसे लापवाही से भरा व महिला का जीवन खतरे में डालने वाला गंभीर सेवा दोष माना। मंच ने महिला चिकित्सक इति माथुर को आदेश दिया है कि वह पूनम को छह लाख रुपए बतौर हर्जाना दें। साथ ही परिवाद व्यय के रूप में दस हजार रुपए अलग से दिए जाएं। राशि का भुगतान एक महीने में करना होगा।

रासायनिक उर्वरकों के अनुदान पर अंकुश जरूरी

'प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर दिए जाने वाले अनुदान पर अंकुश लगाना जरूरी है।' 'कट्स' द्वारा 'प्रोओर्गेनिक-II' परियोजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय हितधारक परिचर्चा के दौरान 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने उक्त विचार व्यक्त करते हुए बताया कि रासायनिक उर्वरकों पर दिया जाने वाला अनुदान सरकार के द्वारा दूसरा बड़ा अनुदान है। जैविक खेती के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.59 प्रतिशत है। 'कट्स' द्वारा यह परियोजना स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन, स्वीडन के सहयोग से राजस्थान के दस जिलों में चलाई जा रही है।

कार्यक्रम में परियोजना के अन्तर्गत अब तक की गई गतिविधियों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया, जिसमें किसान प्रशिक्षण एवं भ्रमण, जागरूकता गतिविधियां, स्कूलों में जैविक गार्डन, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट्स आदि सम्मिलित थीं।

इस अवसर पर कृषि विभाग के निदेशक डॉ. एल.एन.कुमावत ने बताया कि जैविक खेती की मुहिम को उपभोक्ता, किसान और संस्थाओं को समझना होगा तथा एक साथ इसके लिए प्रयास करने होंगे। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, दुर्गापुरा के निदेशक डॉ.वी.एस.यादव ने बताया कि जैविक खेती को बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास उपलब्ध गोबर की खाद को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इनपुट की कोई समस्या नहीं रहेगी।

बीस फीसदी कम हो गई खेती की जमीन

पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों पर हुए संयुक्त राष्ट्र के पहले अध्ययन के अनुसार, जैव विविधता की रक्षा में विफलता के कारण खाद्य उत्पादक भूमि की क्षमता कम हो रही है। जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को कहते हैं।

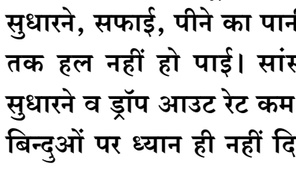

संयुक्त राष्ट्र से जुड़े खाद्य और कृषि संगठन के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा अध्ययन में इस बारे में चेतावनी जारी की है।

जारी रिपोर्ट के मुताबिक, परागण में सहायक भौंरों और तितलियों जैसे कई जीवों का अस्तित्व खतरें में है। इसके अलावा पिछले दो दशकों में दुनिया की 20 प्रतिशत खेती योग्य जमीन कम हो गई है, साथ ही 6000 खेती की प्रजातियों में से कई तेजी से विलुप्त हो रही हैं।

अधूरा रहा आदर्श गांव का सपना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब आदर्श गांव योजना लागू की थी, तब इसका मकसद था कि हर सांसद एक गांव गोद लेकर वहां शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करे। लेकिन प्रदेश के सांसदों द्वारा गोद लिए गए आदर्श गांवों की हालत बेहद खराब है।

प्रदेश के 40 फीसदी गांव ऐसे हैं, जिन्हें गोद लेने के बाद सांसद वहां एक बार भी नहीं गए। वहीं 60 फीसदी सांसदों ने सांसद निधि का एक पैसा भी गोद लिए गए गांवों के विकास पर खर्च नहीं किया। दूरस्थ गांवों में जलस्त्रोत सुधारने, सफाई, पीने का पानी जैसी समस्याएं तक हल नहीं हो पाई। सांसदों ने कुपोषण सुधारने व ड्रॉप आउट रेट कम करने जैसी पांच बिन्दुओं पर ध्यान ही नहीं दिया।

संसद में मिले महिलाओं को आरक्षण

'कट्स' द्वारा 8 मार्च को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय दृष्टिकोण व इस वर्ष के विषय को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की पैरवी करते हुए सभी की सहमति से इस बारे में प्रस्ताव पारित किया गया।

इस अवसर पर 'कट्स' के महामंत्री प्रदीप महता ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस विश्वभर में महिलाओं के राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए लैंगिक समानता पर जोर देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें मुख्यतः राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में महिलाओं की अनिवार्यता हासिल करनी है।

'कट्स' मानव विकास केंद्र सम्मानित

जयपुर स्थित हरिशचंद्र माथुर प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 'कट्स' मानव विकास केंद्र, चित्तौड़गढ़ को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ संस्था पुरस्कार से नवाजा गया है।

समारोह में मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने 'कट्स' के कार्यक्रम अधिकारी मदनलाल कीर को शाल ओढ़ाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं 15 हजार रुपए नकद राशि से सम्मानित किया।

'कट्स' को यह पुरस्कार चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने, उन्हें आयजनक गतिविधियों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने में किए गए सर्वश्रेष्ठ काम पर दिया गया है।

गायें देंगी अब केवल बछड़ी को जन्म

पशुपालक के लिए अत्याधुनिक तकनीक से होने वाले कृत्रिम गर्भाधान से अब गायें केवल बछड़ी को ही जन्म देंगी। इस तकनीक का मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश व हरियाणा के पशुपालक उपयोग कर रहे हैं।

इससे उनके डेयरी फार्मों में गायों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अच्छी नस्लों की गायों के जीन मिलने से बछड़ियों के दूध देने की मात्रा भी पुराने पशुओं से अधिक है। यह तकनीक उन्नत किसानों को काफी राहत दे रही है।

अमरीकी कंपनी ने इसके लिए अब पुणे में प्लांट स्थापित कर दिया है। इससे गायों की विभिन्न प्रजाति के हिसाब से एक से दो हजार रुपए में पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमन सेम्पल उपलब्ध हो सकता है।

बढ़ रहा है डिजिटल खेती का चलन

कृषि क्षेत्र में बढ़ती समस्याओं और अनिश्चितताओं के बीच डिजिटल खेती को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। खर्चीला होने के बावजूद भारत सहित कई एशियाई देशों में इसकी ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है।

डिजिटल खेती में स्वतः काम करने वाले यंत्र, ड्रोन, जीपीएस और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) जैसी तकनीकों की मदद से खेती की जाती है। डिजिटल खेती में बुवाई से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया को बढ़ावा देने सहित लगभग हर जानकारियां शामिल हैं।

नई तकनीकों और उपकरणों के इस्तेमाल के चलते इसमें शुरुआती लागत तो ज्यादा आती है, पर लंबे समय में खेती की लागत काफी घट जाती है।

जलस्त्रोतों को जिंदा करें : हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि वे प्रदेश में जलस्त्रोतों के पुनर्जीवन, अवैध खनन एवं वनों की कटाई रोकने को अपने मिशन में शामिल करें। इसे मनरेगा के कामों में भी शामिल किया जाए। अदालत ने कहा है कि खनन व जल प्रवाह क्षेत्र की सेटेलाइट इमेज ली जाए और गांवों के जलस्त्रोतों व गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएं।

साथ ही अदालत ने इसकी पालना रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी व बी.एल. शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश रामगढ़ बांध सहित प्रदेश के सभी जल बहाव क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण के मामले में दिया।

पति से गिफ्ट मिली संपति स्टाम्प मुक्त

महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी गई अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर अब स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है।

वर्तमान में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती या नातिन को अचल संपत्ति गिफ्ट देने पर संपत्ति के बाजार मूल्य की ढाई प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है। पत्नी या बेटी के मामले में बाजार मूल्य की एक फीसदी या अधिकतम एक लाख तक स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान है। इनमें से जो भी कम हो, वह राशि देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अब पत्नी के मामले में स्टाम्प ड्यूटी पर पूरी छूट देने का निर्देश दिया है।

सुरक्षित हो स्मार्ट उत्पादों की गोपनीयता

'नियामकों को यह देखने की आवश्यकता है कि स्मार्ट उत्पाद सस्ते हों और उनमें गोपनीयता सुरक्षित रहे।' 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में टेलीकॉम नियामक 'ट्राई' की सलाहकार भावना शर्मा ने मुख्यवक्ता के रूप में बोलते हुए यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नियामकों को इस दिशा में अधिक पारदर्शिता से कार्य करने की आवश्यकता है।

वहीं 'कट्स' इटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप महता ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में स्मार्ट फोन और गैजेट के संबंध में ई-कॉमर्स और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के बारे बताया। 'कट्स' इटरनेशनल के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने स्मार्ट उत्पादों की उपलब्धता, डाटा एवं निजी सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उपभोक्ताओं की चिंताओं से अवगत कराया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर